>

Title: Need to provide financial assistance to Parag Dairy in Akbarpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh and to bring it under the control of NDDB.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत और महत्वपूर्ण विषय पर अपना पक्ष इस सदन में रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय के सहयोग आप्रेशन फ्लड योजना के तहत 1971 में 39 जनपदों में सहकारिता उपक्रम स्थायित्व देकर दुग्ध उत्पादक जनता कामगार उपभोक्ता को लाभ पहुंचाया। इससे पहले इसी कार्यक्रम को प्रदेश ग्रामीण अंचल में विकसित करने में शासन दुग्धशाला विकास संघ 1963 में दुग्ध सहकारिता को बंद कर चुका था। 1971 में प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटिड संस्था ने दुग्ध सहकारिता का क्रियान्वयन कराकर दुग्ध उत्पादक किसानों और कामगारों को लाभ और रोजगार दिया था। दुग्धशाला विकास का जवाहर नगर भवन कार्यालय पीसीडीएफ लिमिटिड संस्था का क्रियाकलाप संचालक मंडल द्वारा किया जाता था लेकिन शासन ने 1999 में उसे प्रशासनिक नियंत्रण में लेकर भ्रष्टाचार और घोटालों का बढ़ावा देकर आज पूरे देश में 39 जनपदों में सहारनपुर, अलीगढ़, बरेली, हाथरस, आगरा, मुरादाबाद, फतेहपुर, जेपी नगर दुग्ध संघों की तालाबंदी घोषित कर चुका है।

<u>13.00 hrs.</u>

इसके अलावा कानपुर, बदायूं, कन्नौज, उन्नाव, मैनपुरी, एटा, इटावा, मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर तथा बिजनौर को बंद करने के लिए तैयार हैं। जिसके कारण 43 हजार कर्मचारी सड़क पर आ जायेंगे। पूरे प्रदेश में पीसीडीएफ कर्मचारी संघ हड़ताल पर हैं। उन्हें लगभग एक वर्ष से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उनके परिवार तथा बच्चे बहुत परेशान हैं। 16 करोड़ रुपये प्रदेश में किसानों के बकाया है, जिसके कारण लगभग दो लाख किसान भुखमरी के कगार पर हैं।

सभापति जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को नये उद्योग लगाने की कोई उत्सुकता नहीं है। बल्कि जो पुराने उद्योग थे, उन्हें भी बंद किया जा रहा है, चूंकि आज उनकी जमीनें कीमती हो गई हैं और वे प्राइम लोकेशन में आ गई हैं, इसलिए सरकार उन्हें बेचने जा रही है।

सभापति महोदय : आप अपनी डिमांड बोलिये।

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे कानपुर जनपद में **...**(<u>व्यवधान</u>)

MR. CHAIRMAN : What is your demand to the Central Government?

श्री राजाराम पाल : हमारे कानपुर जनपद में एक बड़ी संस्था थी, जिसके कर्मचारी हड़ताल पर है। इसलिए मैं भारत सरकार के कृषि मंत्री से डिमांड करता हूं कि 43 हजार कर्मचारियों को रोजगार प्रदान करने के लिए तथा दो लाख किसानों के बकाया धन का भुगतान करने के लिए आर्थिक सहायता करें और पीसीडीएफ संस्था को सहकारिता कार्यक्रम के तहत एनडीडीबी के अंतर्गत लेकर इसे संचालित करने का काम करें तथा उत्तर प्रदेश में रोजगार प्रदान करने का काम करें।

SHRI KAMAL KISHOR 'COMMANDO' (BAHRAICH): Sir, I may be also permitted to associate with Shri Rajaram Pal.

MR. CHAIRMAN: Okay. Your name will be associated.